भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *1

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण (शक) को दिया गया)

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत इंटर्नशिप को बढ़ावा देने की कार्यनीतियां

***1. श्री भर्तृहरि महताब**
श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बारैया :

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) आरंभ की है जिसका लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फिनटेक और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए पीएमआईएस के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कार्यानीतियां क्या हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंटर्नशिप करने वालों को भविष्य में नौकरी के लिए बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप प्रासंगिक अनुभव प्राप्त हो सके;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम से कारपोरेट क्षेत्र में, विशेषकर कम प्रतिनिधित्व वाले और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कौशल से संबंधित कमियां प्रभावी तरीके से दूर हो पाएं; और

(ङ) इन पहलों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मापदंड (मीट्रिक्स) क्या हैं और क्या नौकरी हासिल करना इच्छुक युवाओं के अंतिम लक्ष्यों में से एक है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

जारी...2/-

'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप को बढ़ावा देने की कार्यनीतियां' के संबंध में 25 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है , जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट के विवरण वाले दिशानिर्देश https://pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग): पिछले तीन वर्षों में औसत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चयनित शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में विमानन और रक्षा, ऑटोमेटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रसायन उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित कई विविध क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उभरते क्षेत्रों में इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से संपर्क कर सकता है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

(घ): पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं को विभिन्न व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अनुभव और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाएगा। यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिस पर कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट कर सकती हैं और उम्मीदवार अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों का एक समूह पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उन मानदंडों पर आधारित है जो कम रोजगार क्षमता को प्राथमिकता देते हैं और इसका उद्देश्य इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है।

(ङ): पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दिशानिर्देशों में योजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की देखरेख के लिए एक निगरानी और संचालन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और लर्निंग (एमईएल) ढांचे का भी प्रावधान किया गया है ताकि पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिणामों को देखा जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने इसका कार्यान्वयन जारी रहते हुए, आईआईएम बैंगलोर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के साथ मिलकर विभिन्न हितधारकों से फीडबैक एकत्र करने और योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया है।

*****